*** राजस्थान के गांवों में टेलीफोन सुविधाएं**

322. डा0 अबरार अहमद: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। कि :

(क) क्या राजस्थान के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं,

(ख) यदि नहीं, तो राज्य के प्रत्येक जिले में कितने-कितने गांवो में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं,

(ग) क्या सरकार ने राज्य के प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) जिले-वार ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए है। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) सरकार ने निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों से 31 मार्च 2003 तक रॉल आउट दायित्व पूरा करने के लिए कहा है।

विवरण-I

राजस्थान के प्रत्येक जिले के उन गांवों की संख्या जिन्हें टेलीफोन संविधाएं नहीं दी गई है।

क्र0सं	जिले का नाम	सुविधा रहित गांवों की संख्या
1.	अजमेर	45
2.	अलवर	648
3.	बांसबाड़ा	701
4.	बारन	481
5.	बाड़मेर	1016

क्र0 सं0 संख्या	जिले का नाम	सुविधा रहित गांवो की
6.	भरतपुर	590
7.	भीलवाड़ा	550
8.	बीकानेर	273
9.	बूंदी	329
10.	चित्तौड़गढ़	1592
11.	चूरू	272
12.	दौसा	575
13.	धौलापुर	471
14.	डूंगरपुर	334
15.	हनुमानगढ़	1080
16.	जयपुर	726
17.	जैसलमेर	299
18.	जालौर	144
19.	झालावाड़	897
20.	झुंझनू	12
21.	जोधपुर	226
22.	करौली	408
23.	कोटा	210
24.	नागौर	427
25.	पाली	162
26.	राजसमंद	195
27.	सवाई माधोपुर	257
28.	श्रीगंगानगर	1964
29.	सीकर	200
30.	सिरोही	104
31.	टोंक	442
32.	उदयपुर	1225
	जोड़	16855

Telephone Facilities in Rajasthan Villages

†*322. DR. ABRAR AHMED: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether telephone facilities have since been provided in all the villages of Rajasthan;

(b) if not, the number of villages in each district of the State which have not been provided with telephone facilities;

(c) whether Government have set any time-frame for providing telephone facilties in each village of the State; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMUNICAIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ARUN SHOURIE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) The district-wise detals are enclosed at Statement-I *(See* below).

(c) and fd) The Government has asked the private basic service operator to -fulfil the roll out obiligation by 31st March, 2003.

Statement -1

Number of villages in each district of Rajasthan which have not been Drovided with teleDhone facilities

SI. No.	Name of District	Number of Uncovered Villages 45
1	Ajmer	
2	Ah/var	648
3	Banswara	701
4	Baran	481
5	Barmer	1016
6	Bharatpur	590
7	Bhilwara	5-50
8	Bikaner	273
9	Bundi	329

† Original notice of the question was received in Hindi.

SI. No.	Name of District	Number of Uncovered Villages
10	Chittaurgarh	1592
11	Churu	272
12	Dausa	575
13	Dhaulpur	471
14	Dungarpur	334
15	Hanumangarh	1080
16	Jaipur	726
17	Jaisalmer	299
18	Jalore	144
19	Jhalawar	897
20	Jhunjhunu	12
21	Jodhpur	226
22	Karauli	406
23	Kota	210
24	Nagaur	427
25	Pali	162
26	Rajsamand	195
27	Sawai Madhopur	257
28	Sri Ganganagar	1964
29	Sikar	200
30	Sirohi	104
31	Tonk	442
32	Udaipur	1225
	TOTAL:	16855

डा अबरार अहमद: सभापति महोदय माननीय मंत्री जी ने उत्तर में 31 मार्च, 2003 तक राजस्थान में आल आउट दायित्व पूरा करने के लिए कहा है और साथ ही यह भी कहा है कि 16,855 गांव अभी तक राजस्थान में इस सुविधा से रहित है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे पास इसी सत्र में मंत्री जी से पूछे गए दो प्रश्न और उनके उत्तर हैं। एक प्रश्न 19 फरवरी का लोक सभा का अतारांकित प्रश्न संख्या 368 है और उसमें आपने यह बताया है कि राजस्थान में सुविधा रहित गांवों की संख्या 15711 है। तो संख्या घटनी लेकिन यहां तो संख्या बढ़ रही है।

श्री सभापति : पापुलेशन के कारण संख्या बढ़ रही होगी।

डा अबरार अहमद: सभापति महोदय, गांवों की संख्या बढ़ रही है। पापुलेशन की संख्या बढ़ती तो कोई बात नहीं थी।

श्री सभापति : गांवों में ही पापुलेशन बढ़ती है।

डा अबरार अहमद: माननीय मंत्री जी, आपने कहा है कि 31 मार्च तक पूरा होने जा रहा है और हम 31 मार्च के बिल्कुल नजदीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उसमें गांवों की संख्या जो बढ़ रही है, इसके क्या कारण है, दूसरा प्रश्न मेरे पास है 27 फरवरी का जो मैने...

श्री सभापति: आप तो यह पूछें कि 16,000 गांवों को कब तक कनेक्शन द देगें?

श्री अरूण शौरी : सर, माननीय सदस्य का क्वेशचन बहुत अच्छा है। सर, इसमें कारण यह है कि 1991 का जो सैंसस था, उसमें राजस्थन में विलेजिस काउंट किए गए थे...

श्री सभापति : आप गांवों की काउंटिंग को छोड़िए गांवों को कनेक्शन कब तक दे देगें, यह बताइए?

श्री अरूण शौरी : एक सैकिड, सर क्योंकि यह विलेजिस का मामला है, मैं बताना चाहता हूं कि 1991 के सैंसस् में 39,458 विलेजिस गिने गए थे। 2001 का जो सैंसस् था....

श्री सभापति : गांवों की काउंटिंग नहीं, गांव जितने बाकी रह गए हैं उनके बारे में बताइए।

श्री अरूण शौरी : उस सैसस् में विलेजिस ज्यादा हो गए है।

श्री सभापति : गांव ज्यादा कहां हो गए हैं? जो गांव रह गए है उनमें आप कब तक व्यवस्था करेंगे?

श्री अरूण शौरी : सर, उनमें बीएसएनएल तो पूरी कोशिश कर रही है। उसमें दो आपरेटर्स है, स्पेशली कोई कम्पनी है श्याम टेलीलिंक्स, उनकी तरफ से जो कमिटमेंट की गई थी 1998 में, वह बिल्कुल पूरी नहीं हुई। उसके लिए उनकी जो गारंटी थी 8 करोड़ की, वह जब्त कर ली गई है । उनसे एक और एडिशनल बैंक गांरटी मांगी गई थी 50 करोड़ की। कई बार चिट्ठी लिखने के बावजूद उन्होनें इसकी रिप्लाई तक नहीं दी है और मैं उस गारंटी को लिए बिना,अगर वे इस कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो आप देखिए कि उनके 25 करोड़ पड़ें हैं,उस पर मैं जरूर ऐक्शन लूंगा अब वह प्राइवेट कम्पनी कितनी जल्दी कर सकती है यह मैं नहीं कह सकता । बीएसएनएल ने आफर की है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमें कंपंसेशन दीजिए तथा हम पूरा करके देंगे। यह भी हमने पूरी कोशिश की है सर। यह कितनी देर तक हो पाएगा मैं नहीं कह पाऊंगा। मगर पूरी कोशिश है कि इसी साल में हम उसको बहुत अच्छी तरह एक्सटेंड करेंगे राजस्थान में । क्योंकि राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जिसमें प्राइवेट आपरेटर्स ने सबसे कम अपनी गांरटी को फुलफिल किया है ।

श्री सभापति : मुश्किल यह है कि वहां पानी भी नहीं, बिजली भी नहीं और टेलीफोन भी नहीं ।

श्री अरूण शौरी : सर, मुझे इसकी पूरी तवज्जुह है, मैं जरूर इस पर काम करूंगा। ....(व्यवधान)

डा अबरार अहमद : सभापति महोदय मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। सेंसस् की बात वे कह रहे हैं। सवाल का जवाब 19 फरवरी को अभी दिया गया है।

श्री सभापति : गांव के चक्कर में क्योंकि पड़ रहे हो?

डा अबरार अहमद: उसके बाद 27 फरवरी को मेरा खुद का सवाल था, उसके अंदर फिर जवाब दिया । आज 13 मार्च है। इसमें न कोई सेंसस् बढ़ती है, न गांव बढ़ते है। लेकिन वह सेंसस् 1991 की, 1992 की यह सारी बातें कर रहे हैं। मैं उनकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। माननीय सभापति महोदय मेरे ही 27 फरवरी के जवाब में आपने 31 मार्च, 2004 तक पूरा करने के लिए कहा और आपने वहां पर एक लाख चौवालिस हजार एक सौ बहत्तर पेडिंग कनेक्शन बताए। तो तीनों सवालों के अलग –अलग उत्तर है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन सवालों को सरकार बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही है? तीन सवालों में तीन उत्तर तीन संख्या तीन डेटा, हर चीज अलग-अलग इसका सेंसस् से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री सभापति : यह अच्छा है कि पूछने वाले तीन नहीं हैं एक ही है।

श्री अरूण शौरी : सर ऐसी बात ठीक नहीं है। जो प्राइवेट कम्पनी है उसने एश्यूरेंस दिया है कि वह मार्च,2004 तक करेंगे। उनका पास्ट रिकार्ड देख कर मैं उनके बेसिस पर कह दूं कि वह हो जाएगा, तो मैं आपको आश्वासन नहीं दे सकता। मैं उस पर कोशिश जरूर करूगां ।

डा अबरार अहमद : माननीय मंत्री जी के डेटा तो एक रहने चाहिए, फिगर्स तो एक रहनी चाहिए।

श्री संजय निरूपम: जब उन्होंने प्रोमिस पूरा नहीं किया तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिए।

श्री सभापति : एक्शन ले रहे हैं।

श्री अरूण शौरी : सर उनसे 53 करोड़ जब्त किया गया है और इस कम्पनी से 8 करोड़ किया गया है। मैंने आपको अभी बतलाया कि आगे हम क्या करने वाले हैं इस चीज पर।

डा अबरार अहमद: सभापति महोदय सवाल एक है जवाब तीन है कम से कम एक तो जवाब मिले (व्यवधान) सभापति महोदय मैं आपसे बहुत विनम्र आग्रह करना चाहूंगा और आपका सरंक्षण चाहूंगा कि सवाल एक है और उसके तीन उत्तर अलग-अलग हैं। कम से कम जवाब तो एक हो। जब सवाल एक प्रकार के हैं। तो उनका जवाब भी एक होना चाहिए। यह तीनों सवाल 19 फरवरी से 13 मार्च के बीच के हैं। उसमें दो सवाल मेरे खुद के हैं। इन तीनों सवालों पर माननीय मंत्री जी के दिए हुए तीनों जवाब भी यहां मेरे पास हैं। तो किस बात पर विश्वास करें,कौन सी बात को ठीक मानें?

श्री सभापति : ठीक है। आप कम से कम यह उत्तर देख लीजिए कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों हैं?

श्री अरूण शौरी : जो भी डिस्क्रिपेंसी होगी मैं स्टडी करके जरूर सेटिस्फाई करूंगा।

कुमारी मैबल रिबैला : सर मंत्री चेंज होते रहते हैं इस कारण **...(व्यवधान) ...**

श्री सभापति : नेक्सट क्वेश्चन ।

श्री मूल चन्द मीणा : सर, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं ?

श्री सभापति : हो गया, आपकी जगह मैं बोल लिया। तसल्ली रखिए आप ।

Disinvestment of EIL, STC and MUL

*323 SHRI K. RAMA MOHANA RAO: Will the Minister of DISINVESTMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are thinking of disinvesting the Engineers India Ltd., State Trading Corporation and the Maruti Udyog Ltd. by the end of this year;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any process has been started in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DISINVESTMENT (SHRI ARUN SHOURIE): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Govenment has decided to disinvest 51 % equity of Engineers India Limited (EIL) through strategic sale and 10% equity of EIL in favour